हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 27फ़रवरी 2026, समय 1810 (10 मिनट)

मुख्य समाचार :-

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया।

2. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- कि एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तक मामले मे मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।

3. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हकों के प्रति सजग है ।

4. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा का चरखी दादरी मे प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई।

5. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर बल दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त" विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।

राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोड मैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो इज-

ऑफ-डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार की गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत इरादों तक ही सीमित न रहकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया है कि भारत का विकास राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क और विद्युत प्रणालियों जैसी ठोस संपत्तियों को तैयार करके ही संभव होगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है।

11 साल पहले पब्लिक .... के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में यह बढ़कर लगभग 12 लाख करोड रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।

श्री मोदी ने कहा कि जब उद्योग, शिक्षा जगत, विश्लेषक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर सोचते हैं, तो योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होता है और सटीक परिणाम मिलते हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर खेद व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।

जो घटना हुई है, उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उस पर उसको और इंक्वारी किया जाएगा, जो भी व्यक्ति से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न हैं। उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे यह गलती ना हो, न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। मैं मानता हूं हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की यही सुंदरता है। न्यायपालिका के आदर्श स्थान है, न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान है।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय वाली कक्षा 8 की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हकों के प्रति सजग है और उनकी फसल की खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खेत से ही गेट पास की सुविधा दी है।

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में, कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला के नकली गेट पास बनाकर फर्जी तरीके से हरियाणा की मंडियों में लाकर धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के आरोप का जवाब दे रहे थे।

विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार पर प्रदेश के किसानों का हक मारे जाने को लेकर कहा –

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा के दौरान आज चरखी दादरी जिले के गांव रानीला स्थित परीक्षा केंद्र से गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी मिलते ही हरियाणा विद्यालय

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने केंद्र पर छापेमारी की और इस में संलिप्त छात्रों, शिक्षकों और सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध कारवाई शुरू की।

डा. पवन कुमार ने बताया कि जैसे ही प्रश्न पत्र की फोटो वायरल हुई, प्रश्न पत्र पर अंकित क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए चंद मिनटों में यह पहचान कर ली गई कि पेपर किस केंद्र और किस कमरे से बाहर आया है। उन्होंने बताया कि दो छात्रों और दो सुपरवाइजर समेत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुपरवाइजर विनोद और राजबीर को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। वही केंद्र पर तैनात पूरे स्टाफ को भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। साथ ही केंद्र अधीक्षक और उप-केंद्र अधीक्षक के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा इसके अलावा पूरे परीक्षा केंद्र को ही दूसरी जगह भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। दादरी के पुलिस अधीक्षक ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में हेड कांस्टेबल नरेश और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल जयकिशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बोंद कलां थाने के एसएचओ और संबंधित एसपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पंजाब के राज्यपाल एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज 'सशक्त बाल महोत्सव–3.0' के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्री कटारिया ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने पर बल दिया तथा शिक्षकों और मार्गदर्शकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 -पोक्सो के अंतर्गत तैयार महोत्सव चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसका उद्देश्य बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग

के प्रयासों की सराहना की। एक माह तक चलने वाला महोत्सव चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपने 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सग्गा एवं समाना बाहु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्री ने आज विधानसभा में एक सवाल का जवाब में यह जानकारी दी।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गांव सग्गा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य लगभग 38 प्रतिशत पूरा होने के बाद एजेंसी द्वारा काम रोक दिया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त एजेंसी का अनुबंध 5 जुलाई 2023 को समाप्त कर दिया गया । संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत, निविदा प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है और भवन का शेष निर्माण कार्य छह महीने के भीतर पुनः आरंभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने गांव समाना बाहु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रुके हुए निर्माण कार्य से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए बताया कि संविदा एजेंसी ने 70 प्रतिशत कार्य पूरा करने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया था और लोक निर्माण विभाग के साथ विवाद को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। विभाग द्वारा एजेंसी का अनुबंध 20 जून 2024 को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पीएचसी के भवन निर्माण का कार्य पुनः आरंभ होने में लगभग छह महीने लगेंगे और उसके बाद इसे पूर्ण करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।